

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

पौड़ी गढ़वाल

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: २५ नवम्बर, 2011

विषय:—स्निग्धा कल्चरल सेन्टर, नई दिल्ली को दयालपुरम, सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल में चिकित्सालय की स्थापना हेतु कुल 2.543 है० भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-4098/11-रीडर (2010-11) दिनांक-20.9.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, स्निग्धा कल्चरल सेन्टर, नई दिल्ली को दयालपुरम, सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल में चिकित्सालय की स्थापना हेतु कुल 2.543 है० भूमि कय की अनुमति, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी सहमति/अनापत्ति एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(I) के अन्तर्गत तथा आपके द्वारा संस्तुत खाता संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- केता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (चिकित्सालय की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित

जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि क़य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग मात्र उपरोक्त प्रयोजनों हेतु ही किया जायेगा। इसके साथ ही, प्रस्तावित भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्यों हेतु किये जाने पर, उक्त भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

8- संस्था द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अर्थात् बी0पी0एल0 कार्ड धारको को निशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जायेगी।

9- संस्था द्वारा, आपदा प्रबन्धन, अकास्मिक दुर्घटनाएं संक्रामक रोगों आदि की रोकथाम के लिए, राज्य सरकार को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

10- संस्था द्वारा, राज्य सरकार की नीति के अनुरूप कार्य किया जायेगा।

11- संस्थान की स्थापना, संचालन एवं प्रचार प्रसार संस्था को अपने संसाधनों से करना होगा तथा इसमें राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

12- चिकित्सा विभाग, राज्य सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा।

13- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क़य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

16- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

17- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश की एक प्रति अनिवार्य रूप से शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ०प०सं०-२५४७ / सम्दिनांकित 2011

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- अध्यक्ष, स्निग्धा कल्चरल सेन्टर पंजीकृत कार्यालय B-1 141 जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(संतोष बडोनी)

अनुसचिव।